

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Negotiations are yet to be completed on the assistance which Italy may provide over and above this credit of Rs. 5.5 crores.

**PROPOSAL FOR GIVING RELIEF TO NATIONAL MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION TO OFFSET LOSSES INCURRED OVER MINES**

4837. SHRI CHENGALRAYA

NAIDU :

SHRI MAYAVAN :

SHRI R. BARUA :

SHRI N. R. LASKAR :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether the Central Government has considered the proposal for giving relief to the National Mineral Development Corporation to offset the losses incurred over the mines;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATH RAO) :

(a) to (c). The proposal for giving relief to the National Mineral Development Corporation Limited, to offset the losses incurred on iron ore projects is under consideration of the Government. The nature and manner of the relief will be known when a final decision is taken.

**INCREASE IN WORLD BANK INTEREST RATE**

4838. SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

SHRI MAYAVAN :

SHRI N. R. LASKAR:

SHRI R. BARUA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that World Bank has raised the lending rate to a new peak of 7 per cent from 6.5 per cent;

(b) whether this increase will be a great burden to India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) In July, 1969, the World Bank took a decision to raise the Bank's lending rate from 6.50 per cent to 7 per cent on loans to be made after July 31, 1969.

(b) and (c). The increase in the Bank's lending rate is not expected to impose any substantially large additional burden on India, since a very large part of the assistance received by India from the World Bank Group is received from the International Development Association, which charges no interest on its loans but only a service charge of 3/4 per cent.

**राजस्थान में पाइपों के जरिये सिंचाई सुविधायें**

4839. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी सिंचाई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि राजस्थान में पाईप बिछाकर वहां सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खुद अपने तरीके से इस बात का पता लगाया है कि राजस्थान के लिये यह प्रणाली कहां तक उपयुक्त होगी; और

(ग) क्या यह प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर ही अपनाई जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है।

सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित मिचरई नहरें विशाल मात्रा में जल की निकासी करती हैं और उनमें गैर-डाब (नॉन-फ्लो) प्रवाह होता है। इसलिए उन्हें खुली हुई कच्ची नालियों के रूप में रखा जाता है जो पाईप लाइनों की तुलना में बहुत सस्ती पड़ती हैं। जहां भी पानी की हानि से रक्षा करनी होती है वहां इन कच्ची नालियों में पलस्तर भी कर दिया जाता है।

### वित्त मंत्रालय में बैंकिंग सैल के लिए कर्मचारियों की भर्ती

4840. श्री रामावतार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अपने मंत्रालय में एक बैंकिंग सैल स्थापित करने के लिये अलग कर्मचारियों की भर्ती की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस मंत्रालय के अधीन स्थापित नये बैंकिंग विभाग का कार्यालय मंत्रालय में ही रहेगा अथवा किसी अलग इमारत में; और

(ग) यदि वह किसी अलग इमारत में होगा तो उस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बैंकिंग विभाग में कर्मचारी भर्ती करने का तरीका वही है जो इस मंत्रालय के अन्य विभागों अथवा भारत सरकार के किसी अन्य मन्त्रालय में अपनाया जाता है।

(ख) बैंकिंग विभाग के लिये स्थान की व्यवस्था उस इमारत के एक भाग में की गयी है जो इस समय वित्त मंत्रालय के पास है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

### दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरिजनों का पुनर्वास

4841. श्री प० ला० बाहूपाल :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बरसाती नाला पर रहने वाले हरिजनों को हुमायपुर और कैलाश कालोनी में जंगपुरा तथा निजामुद्दीन के बीच बसाने का निर्णय किया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्राधिकरण ने इन लोगों को अब तक कोई स्थान नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). झुग्गी निवासियों के पुनर्वास का प्रश्न तभी उठता है जबकि किसी विशेष स्थान से झुग्गियाँ हटाई जाती हैं। किसी क्षेत्र की सफाई तथा उसके फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की प्राथमिकता अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि के विकास की आवश्यकता, यात्रायत सुरक्षा की आवश्यकता आदि।

इस समय प्रश्नाधीन क्षेत्र से झुग्गियाँ हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतएव इन झुग्गी निवासियों को वैकल्पिक स्थान (माईट) के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

### राजस्थान में पलाना कोयला खान का बन्द होना

4842. श्री प० ला० बाहूपाल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :